विमुद्रीकरण और सीएनबीसी आवाज़
Demonetization and CNBC Awaaz

लघु शोध-प्रबंध
(एम. फिल. उपाधि हेतु)

सत्र: 2016-17

ज्ञान शांति मैत्री

शोध निर्देशक
डॉ. धरवेश कठेरिया
(सहायक प्रोफेसर)
जनसंचार विभाग

शोधार्थी
पदमा वर्मा
एम. फिल. जनसंचार
पंजी.क्र.- 2016/05/208/018

जनसंचार विभाग
मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
Gandhi Hills, Wardha- 442001 (Maharashtra), India.

अध्यायवार विवरण

प्रस्तुत शोध 'विमुद्रीकरण और सीएनबीसी आवाज़' विषय को कुल छः अध्यायों के अंतर्गत स्वरूप प्रदान किया गया है। अध्याय क्रमवार संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

अध्याय: एक
शोध का निरूपण

प्रस्तुत अध्याय में शोध से संबन्धित उद्देश्य, उपकल्पना, शोध की प्रासंगिकता, शोध क्षेत्र एवं सीमाएं एवं शोध में उपयोग होने वाली प्रविधियों का वर्णन किया गया है। साहित्य पुनरावलोकन के अंतर्गत शोध के दौरान अध्ययन किए गए पुस्तक, रिपोर्ट, लेख आदि का उल्लेख किया गया है तथा भविष्य में शोध की उपयोगिता को बताने की कोशिश की गई है।

अध्याय: दो
भारतीय अर्थव्यवस्था: विमुद्रीकरण का सफर

प्रस्तुत अध्याय में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबन्धित तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है। इतिहास में भारत की आर्थिक नीति व स्थिति को समझाने की कोशिश की गई है तथा भारत में विमुद्रीकरण के सफर व भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान परिदृश्य पर भी प्रकाश डाला गया है।

अध्याय: तीन
सरकार: कालेधन पर सर्जिकल स्ट्राइक की नीति

प्रस्तुत अध्याय में कालेधन समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम पर प्रकाश डाला गया है। इसमे सर्वप्रथम भारतीय रिजर्व बैंक को संक्षिप्त में समझाया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था में बाधा बनने वाली कालेधन की अर्थव्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की गई है। विमुद्रीकरण पर सरकार की गोपनीयता, कालेधन पर सर्जिकल स्ट्राइक, नकली नोट से छुटकारा, नक्सली गतिविधियों पर रोक और भ्रष्टाचार एवं अपराधिक कार्यों पर रोक आदि उपशीर्षकों पर प्रकाश डाला गया है।

अध्याय: चार
विमुद्रीकरण: कैशलेस अर्थव्यवस्था और डिजिटल भुगतान

प्रस्तुत अध्याय में भारत में विमुद्रीकरण के बाद कैशलेस अर्थव्यवस्था और डिजिटल भुगतान पर प्रकाश डाला गया है। विमुद्रीकरण के बाद डिजिटल भुगतान में हुई बढ़ोत्तरी, जन-धन खाते की उपयोगिता, विमुद्रीकरण से देश में नोटों की कमी, बैंक और एटीएम मशीनों का योगदान और आम जनता के लिए सरकार द्वारा लाई गई नई-नई स्कीमों पर प्रकाश डाला गया है।

अध्याय: पांच
CNBC आवाज़: विमुद्रीकरण की खबरों का प्रसारण और प्रस्तुति

प्रस्तुत अध्याय में CNBC आवाज़ चैनल पर विमुद्रीकरण से संबन्धित खबरों के प्रसारण पर प्रकाश डाला गया है। सर्वप्रथम CNBC आवाज़ चैनल की स्थापना और शुरुआती दौर को अध्याय में वर्णित किया गया है। विमुद्रीकरण के दौरान जनता को जागरूक करने हेतु चैनल द्वारा प्रसारित किए गए कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला गया है।

अध्याय: छ:
तथ्यों का संकलन, विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण

प्रस्तुत अध्याय में CNBC आवाज़ पर प्रसारित कार्यक्रम 'आवाज़ अड्डा' पर विमुद्रीकरण से संबन्धित खबरों के अध्ययन में लिए गए 15 वीडियो के विश्लेषण को शामिल किया गया है। इसमें विमुद्रीकरण से संबन्धित विशेषज्ञों की राय को भी शामिल किया गया है। CNBC आवाज़ के प्रबंध संपादक आलोक जोशी से विमुद्रीकरण से संबन्धित प्रश्नों पर लिए गए साक्षात्कार का भी विश्लेषण किया गया है।

निष्कर्ष:

विषय से संबन्धित तथ्य, रिपोर्ट, वीडियो के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष दिया गया है।

सुझाव:

अध्ययन के पश्चात विमुद्रीकरण की स्थिति एवं भविष्य में सुधार से संबंधित सुझाव दिए गए हैं।

भूमिका

भारत को सोने की चिड़िया वाला देश कहा जाता था। भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में गिना जाता था। उस समय भारत की जीडीपी विश्व के कुल जीडीपी का 32.9% था। धीरे-धीरे भारत की अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर नीचे गिरता गया। सन 1000 में 28.9%, 1700 में 24.4% तथा इसके बाद भारत की आर्थिक विकास दर लगातार गिरती गई। 1970 के दशक के समाप्ति तक जीडीपी की वार्षिक विकास दर 5% से कम रही और 90 के दशक में विकास दर 5.68% रही। सन 2000 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में लगातार उतार-चढ़ाव की स्थिति बनती रही। किसी भी देश में अर्थव्यवस्था की विकास का अनुमान बाज़ारों में मुद्राओं के परिसंचरण से लगाया जाता है।

यदि किसी कारण से मुद्रा का प्रवाह रुकता है तो देश के अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों एवं मॉडलों में आय का परिपत्र प्रवाह, आर्थिक अधिशेष, उदासीनता वक्र, व्यष्टि अर्थव्यवस्था आदि प्रमुख हैं। इन्हीं सिद्धांतों पर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था कार्य करती है। देश की आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत विमुद्रीकरण भी एक प्रक्रिया है जिसमें पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्राओं को स्थान दिया जाता है। 8 नवंबर 2016 को हुए विमुद्रीकरण के बाद भारत की अर्थव्यवस्था कुछ समय के लिए डगमगा गई थी। नोटबंदी के समय शेयर बाज़ार में गिरावट देखी गई और रियल स्टेट, ऑटो मोबाइल, टेलीकॉम जैसे क्षेत्र ज्यादा प्रभावित हुए। कुछ दिनों के लिए बाज़ार में मंदी का दौर रहा क्योंकि लोगों के हाथों में पैसे नहीं थे। ऐसे समय में डिजिटल ट्रांजेक्शन की ओर लोगों ने रूख किया। रुपए कार्ड के ट्रांजेक्शन में 3 गुना की बढ़ोत्तरी हुई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्वाइप मशीन से 10-12 लाख प्रतिदिन ट्रांजेक्शन की वृद्धि देखने को मिली है। नोटबंदी के दौर में नकदी के विकल्पों को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी।

नोटबंदी के समय डेबिट कार्ड के इस्तेमाल में 111% की वृद्धि हुई। नोटबंदी से नगर निगम को बहुत फायदा हुआ क्योंकि लोगों ने पुराने नोटों में अपने म्यूनिसिपल टैक्स चुकाए हैं जिससे 47 नगर निगमों के टैक्स में 268% की वृद्धि हुई। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार नोटबंदी ने भारत को डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बाकी देशों से 3 वर्ष आगे पहुंचा दिया। मोबाइल वॉलेट, मोबाइल बैंकिंग, पेपर वाउचर, PPI कार्ड में 122% की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। रिजर्व बैंक के रिपोर्ट में देश में विमुद्रीकरण का सकारात्मक प्रभाव दिखा। रिपोर्ट के अनुसार विमुद्रीकरण ने न सिर्फ कालेधन पर चोट किया बल्कि भ्रष्टाचार के जड़ों तक प्रहार किया। डिजिटल बैंकिंग में पैसे आने से आम जनता को और सरकार को सीधे फायदा पहुंचेगा। विमुद्रीकरण के कारण देश की अर्थव्यवस्था की भी सफाई हो रही है। नोटबंदी के बाद से आंकड़ो के अनुसारकरीब 2 लाख फर्जी कंपनियों का पता चला है जिससे कालेधन की लेन-देन होती रही है। टैक्स रिटर्न में भी 56 लाख नए करदाताओं का पता चला साथ ही 18 लाख ऐसे लोगों का पता चला जिनकी संपत्ति उनकी आय से ज्यादा है।

आईटी विभाग और जांच एजेंसियां भी कालेधन को निकालने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज आमजन में कैशलेस के प्रति भी जागरूकता बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक 4 अगस्त तक आम लोगों के पास 14, 75, 400 करोड़ की

करेंसी थी जो कि विमुद्रीकरण के ठीक पहले की करेंसी के मुक़ाबले ये 1, 89, 200 करोड़ रुपए कम है। अर्थात देश विमुद्रीकरण के कारण कैशलेस तंत्र की तरफ आगे बढ़ रहा है

निष्कर्ष

किसी भी देश में मुद्रा का संचरण जितनी तेजी से होता है उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही तेजी से बढ़ती है। डिजिटल तरीके से किए गए लेन-देन में मुद्रा के संचरण का प्रवाह बढ़ जाता है। यह प्रवाह बैंकिंग प्रणाली से होकर गुजरता है जिससे देश की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आती है और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।

प्रसारित कार्यक्रम 'आवाज़ अड्डा' के कुल 15 वीडियो में कुल 99 विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था। इनमें से 16 विशेषज्ञों ने पूर्णतः विमुद्रीकरण के पक्ष में अपने मत रखे जिनमें बीजेपी प्रवक्ता प्रमुख रूप से शामिल थे। 25 विशेषज्ञों ने विमुद्रीकरण के संबंध में पूरी तरह सरकार के विपक्ष में मत रखे जिनमें विपक्षी दल जैसेकांग्रेस, आप, टीएमसी, बीएसपी के नेता शामिल थे। पैनल में 24 विशेषज्ञों ने सरकार के फैसले पर सहमति जताई और केवल 08 विशेषज्ञों ने असहमति जताई वहीं 26 विशेषज्ञों ने सरकार के इस फैसले पर सामान्य विचार रखें। शोध विश्लेषण के आधार पर देखें तो सीएनबीसी आवाज़ में प्रसारित आवाज़ अड्डा कार्यक्रम के कुल 15 वीडियो के पैनल में सम्मिलित 99 विशेषज्ञों में से केवल 08 विशेषज्ञों ने ही सरकार के विमुद्रीकरण के फैसले पर असहमति व्यक्त की है वहीं 24 विशेषज्ञों ने सहमति व 26 विशेषज्ञों ने सामान्य विचार दिए हैं। प्राप्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि पैनल में सम्मिलित ज्यादातर विशेषज्ञों विमुद्रीकरण के फैसले पर सरकार को समर्थन किया।

सीएनबीसी आवाज़ के रिपोर्ट के अनुसार देश में 103 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन, 35 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन, 108 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड और सिर्फ 50 करोड़ लोगों के पास इन्टरनेट कनेक्शन है। इसके अलावा ज़्यादातर लोग कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ मुद्रा निकासी के लिए करते हैं।

विमुद्रीकरण की पूर्व तैयारी नहीं होने की वजह से नए नोटों की छपाई में कमी आई। नए नोटों का आकार छोटा होने के कारण देश की आधे से अधिक एटीएम मशीनों की रिकेलिब्रेशन (सुधार) का काम चल रहा था जो विमुद्रीकरण की आधी-अधूरी तैयारी को दर्शाता है।

अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर बिन्दुवार निष्कर्ष इस प्रकार है-

- भारत में कालाधन रियल स्टेट, गोल्ड और स्विस बैंकों में हैं जिस पर विमुद्रीकरण का कोई खास असर नहीं पड़ा जबकि देश की आम जनता जो गाँवों में हैं उनका जन-जीवन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ।
- सीएनबीसी आवाज़ में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार देश में 140 लोगों की मौत कतारों में खड़े होने की वजह से हो गई।
- सरकार का बार-बार विमुद्रीकरण के नियम बदलना ही विमुद्रीकरण की तैयारी को फ़ेल साबित कर रहा था। विपक्षी पार्टियों के अनुसार यह फैसला सहीं था परंतु क्रियान्वयन ठीक नहीं हुआ।

- बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से जन-धन खाते में ही अधिकाधिक कालाधान वापस आ गया जिसे सरकार की सफलता के रूप में देखा जा रहा है।
- आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार केवल 16,000 करोड़ रुपए के पुराने नोट ही बैंक में नहीं आए हैं जो कुल मुद्रा का केवल 1 प्रतिशत है। आंकड़ों पर गौर करें तो 99% मुद्रा वापस आ चुका है। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि कालाधन निकालने के लिए विमुद्रीकरण का फैसला सफल रहा।
- विमुद्रीकरण से देश में टैक्स चोरी, जाली नोट और आतंकवादी गतिविधियों पर प्रहार हुआ।
- विमुद्रीकरण के दौरान लोगों का रुख डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़ा लेकिन नए नोटों की तरलता के साथ हालात सामान्य होने पर डिजिटल पेमेंट में लगातार गिरावट देखी गई।
- सीएनबीसी आवाज़ चैनल के ट्विटर पोल पर जनता से पूछे गए नोटबंदी से संबन्धितसभी प्रश्नों पर देश की आधे से अधिक जनता ने सरकार के साहस भरे फैसले का समर्थन किया है जिससे पता चलता है कि आधे से अधिक जनता ने विमुद्रीकरण के फैसले पर सरकार का समर्थन किया।
- विमुद्रीकरण के बाद की प्रक्रिया को सफल बनाने में बैंको की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

शोध-सारांश

किसी भी देश में मुद्रा का संचरण जितना तेजी से होता है उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही तेजी से बढ़ती है। डिजिटल तरीके से किए गए लेन-देन में मुद्रा के संचरण का प्रवाह बढ़ जाता है। यह प्रवाह बैंकिंग प्रणाली से होकर गुजरता है जिससे देश की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आती है और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।

प्रसारित कार्यक्रम 'आवाज़ अड्डा' के कुल 15 वीडियो में कुल 99 विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था। इनमें से 16 विशेषज्ञों ने पूर्णतः विमुद्रीकरण के पक्ष में अपने मत रखे जिनमें बीजेपी प्रवक्ता प्रमुख रूप से शामिल थे। 25 विशेषज्ञों ने विमुद्रीकरण के संबंध में पूरी तरह सरकार के विपक्ष में मत रखे जिनमें विपक्षी दल जैसे कांग्रेस, आप, टीएमसी, बीएसपी के नेता शामिल थे। पैनल में 24 विशेषज्ञों ने सरकार के फैसले पर सहमति जताई और केवल 08 विशेषज्ञों ने असहमति जताई वहीं 26 विशेषज्ञों ने सरकार के इस फैसले पर सामान्य विचार रखे। शोध विश्लेषण के आधार पर देखें तो सीएनबीसी आवाज़ में प्रसारित आवाज़ अड्डा कार्यक्रम के कुल 15 वीडियो पैनल में सम्मिलित 99 विशेषज्ञों में से केवल 08 विशेषज्ञों ने ही सरकार के विमुद्रीकरण के फैसले पर असहमति व्यक्त की है वहीं 24 विशेषज्ञों ने सहमति व 26 विशेषज्ञों ने सामान्य विचार दिए हैं। प्राप्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि पैनल में सम्मिलित ज्यादातर विशेषज्ञों ने विमुद्रीकरण के फैसले पर सरकार को समर्थन किया।

सीएनबीसी आवाज़ के रिपोर्ट के अनुसार देश में 103 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन, 35 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन, 108 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड और सिर्फ 50 करोड़ लोगों के पास इन्टरनेट कनेक्शन है। इसके अलावा ज़्यादातर लोग कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ मुद्रा निकासी के लिए करते हैं।

विमुद्रीकरण की पूर्व तैयारी नहीं होने की वजह से नए नोटों की छपाई में कमी आई। नए नोटों का आकार छोटा होने के कारण देश की आधे से अधिक एटीएम मशीनों की रिकेलिब्रेशन (सुधार) का काम चल रहा था जो विमुद्रीकरण की आधी-अधूरी तैयारी को दर्शाता है।

शोध की प्रासंगिकता:

सामाजिक संरचना में किसी भी विषय-वस्तु में एकाएक बदलाव होने पर समाज उसे स्वीकार नहीं करता है। त्वरित हुए बदलाव को आमजन आसानी से आत्मसात नहीं कर पाते हैं। नोटबंदी के समय में भी कुछ इसी तरह के उदाहरण देखने को मिले हैं। अर्थशास्त्री अरूण कुमार ने कहा कि जैसे ही अर्थव्यवस्था सामान्य होगी, दोबारा से कालाधन जेनरेट होगा। कालेधन पर अंकुश लगाने का यह तरीका सहीं नहीं है। इस तरह से कई अर्थशास्त्रियों ने नोटबंदी को देश के पक्ष में वरदान बताया तो कई अर्थशास्त्रियों ने अभिशाप भी बताया। शोध की दृष्टि से विमुद्रीकरण के प्रभाव, सामाजिक समस्याएं, वैश्विक पटल पर नोटबंदी का असर, भारतीय बाजार, विश्व बाजार, भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट आदि को रेखांकित करना है। नोटबंदी निर्णय को जिस तरीके से पेश किया गया था उसके एक साल बाद भी इस तरह का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

के कथनों के अनुसार कालाधन खत्म करना, भ्रष्टाचार मिटाना जैसी बातें सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गई। उपर्युक्त बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए भविष्य में भी यह शोध प्रासंगिक बना रहेगा।

शोध के उद्देश्य:

शोध कार्य विषय- **'विमुद्रीकरण और सीएनबीसी आवाज़'** में शोध के निम्न उद्देश्य हैं -

- भारत में (2016) विमुद्रीकरण के बाद की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
- विमुद्रीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव एवं मीडिया प्रस्तुति का अध्ययन।
- विमुद्रीकरण से उत्पन्न सामाजिक असंतुलन एवं जागरूकता का अध्ययन करना।
- **CNBC** आवाज़ पर प्रसारित विमुद्रीकरण के ख़बरों की प्रस्तुतिकरण का अध्ययन।

शोध उपकल्पना:

शोध कार्य विषय-**'विमुद्रीकरण और सीएनबीसी आवाज़'** में निम्न बिंदु उपकल्पना के रूप में हैं -

- विमुद्रीकरण से कालेधन पर लगाम लगा और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिला ।
- विमुद्रीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है।
- विमुद्रीकरण की ख़बरों को CNBC आवाज़ ने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया।
- CNBC आवाज़ ने विमुद्रीकरण के प्रति आमजन में जागरुकता फैलाई।

शोध क्षेत्र एवं सीमाएं:

शोध विषय-**'विमुद्रीकरण और सीएनबीसी आवाज़'** में शोध के अध्ययन में बिजनेस चैनल 'CNBC आवाज़' पर विमुद्रीकरण की प्रस्तुतिकरण के अंतर्वस्तु विश्लेषण को अध्ययन में शामिल किया है। शोध की सीमाओं में 8 नवम्बर 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक के समयांतराल के महत्वपूर्ण समय को शामिल किया गया है। उक्त समय के अंतर्गत विमुद्रीकरण से संबंधित प्राईम टाईम(आवाज़ अड्डा) में प्रसारित कार्यक्रमों को शोध विश्लेषण हेतु आधार बनाया गया है।

शोध प्रविधि:

प्रस्तावित शोध कार्य विषय- **'विमुद्रीकरण और सीएनबीसी आवाज़'** में उपयोग की गई प्रविधि इस प्रकार है-

- **अवलोकन पद्धति**
- **अंतर्वस्तु विश्लेषण**

- **साक्षात्कार**

अध्यायवार संक्षिप्त विवरण:

अध्याय संक्षेपिका

प्रस्तुत शोध 'विमुद्रीकरण और सीएनबीसी आवाज़' विषय को कुल छ: अध्यायों के अंतर्गत स्वरूप प्रदान किया गया है। अध्याय क्रमवार संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

अध्याय: एक
शोध का निरूपण

प्रस्तुत अध्याय में शोध से संबन्धित उद्देश्य, उपकल्पना, शोध की प्रासंगिकता, शोध क्षेत्र एवं सीमाएं एवं शोध में उपयोग होने वाली प्रविधियों का वर्णन किया गया है। साहित्य पुनरावलोकन के अंतर्गत शोध के दौरान अध्ययन किए गए पुस्तक, रिपोर्ट, लेख आदि का उल्लेख किया गया है तथा भविष्य में शोध की उपयोगिता को बताने की कोशिश की गई है।

अध्याय: दो
भारतीय अर्थव्यवस्था: विमुद्रीकरण का सफर

प्रस्तुत अध्याय में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबन्धित तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है। इतिहास में भारत की आर्थिक नीति व स्थिति को समझाने की कोशिश की गई है तथा भारत में विमुद्रीकरण के सफर व भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान परिदृश्य पर भी प्रकाश डाला गया है।

अध्याय: तीन
सरकार: कालेधन पर सर्जिकल स्ट्राइक की नीति

प्रस्तुत अध्याय में कालेधन समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम पर प्रकाश डाला गया है। इसमे सर्वप्रथम भारतीय रिजर्व बैंक को संक्षिप्त में समझाया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था में बाधा बनने वाली कालेधन की अर्थव्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की गई है। विमुद्रीकरण पर सरकार की गोपनीयता, कालेधन पर सर्जिकल स्ट्राइक, नकली नोट से छुटकारा, नक्सली गतिविधियों पर रोक और भ्रष्टाचार एवं अपराधिक कार्यों पर रोक आदि उपशीर्षकों पर प्रकाश डाला गया है।

अध्याय: चार
विमुद्रीकरण: कैशलेस अर्थव्यवस्था और डिजिटल भुगतान

प्रस्तुत अध्याय में भारत में विमुद्रीकरण के बाद कैशलेस अर्थव्यवस्था और डिजिटल भुगतान पर प्रकाश डाला गया है। विमुद्रीकरण के बाद डिजिटल भुगतान में हुई बढ़ोत्तरी, जन-धन खाते की उपयोगिता, विमुद्रीकरण से देश में नोटों की कमी, बैंक और एटीएम मशीनों का योगदान और आम जनता के लिए सरकार द्वारा लाई गई नई-नई स्कीमों पर प्रकाश डाला गया है।

अध्याय: पांच
CNBC आवाज़: विमुद्रीकरण की खबरों का प्रसारण और प्रस्तुति

प्रस्तुत अध्याय में CNBC आवाज़ चैनल पर विमुद्रीकरण से संबन्धित खबरों के प्रसारण पर प्रकाश डाला गया है। सर्वप्रथम CNBC आवाज़ चैनल की स्थापना और इसके शुरुआती दौर को अध्याय में वर्णित किया गया है। विमुद्रीकरण के दौरान जनता को जागरूक करने हेतु चैनल द्वारा प्रसारित किए गए कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला गया है। अंत में विमुद्रीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था व आम जनता पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी प्रकाश डाला गया है।

अध्याय: छ:
तथ्यों का संकलन, विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण

प्रस्तुत अध्याय में CNBC आवाज़ चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम 'आवाज़ अड्डा' पर विमुद्रीकरण विषय से संबन्धित खबरों के अध्ययन में लिए गए 15 वीडियो के विश्लेषण को शामिल किया गया है। इसमें विमुद्रीकरण से संबन्धित विशेषज्ञों की राय को भी शामिल किया गया है। CNBC आवाज़ के प्रबंध संपादक आलोक जोशी से विमुद्रीकरण से संबन्धित प्रश्नों पर लिए गए साक्षात्कार का भी विश्लेषण किया गया है।

निष्कर्ष:

विषय से संबन्धित तथ्य, रिपोर्ट, वीडियो के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्न हैं-

- भारत में कालाधन रियल स्टेट, गोल्ड और स्विस बैंकों में हैं जिस पर विमुद्रीकरण का कोई खास असर नहीं पड़ा जबकि देश की आम जनता जो गाँवों में हैं उनका जन-जीवन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ।
- सीएनबीसी आवाज़ में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार देश में 140 लोगों की मौत कतारों में खड़े होने की वजह से हो गई।
- सरकार का बार-बार विमुद्रीकरण के नियम बदलना ही विमुद्रीकरण की तैयारी को फ़ेल साबित कर रहा था। विपक्षी पार्टियों के अनुसार यह फैसला सहीं था परंतु क्रियान्वयन ठीक नहीं हुआ।
- बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से जन-धन खाते में ही अधिकाधिक कालाधान वापस आ गया जिसे सरकार की सफलता के रूप में देखा जा रहा है।
- आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार केवल 16,000 करोड़ रुपए के पुराने नोट ही बैंक में नहीं आए हैं जो कुल मुद्रा का केवल 1 प्रतिशत है। आंकड़ों पर गौर करें तो 99% मुद्रा वापस आ चुका है। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि कालाधन निकालने के लिए विमुद्रीकरण का फैसला सफल रहा।
- विमुद्रीकरण से देश में टैक्स चोरी, जाली नोट और आतंकवादी गतिविधियों पर प्रहार हुआ।
- विमुद्रीकरण के दौरान लोगों का रुख डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़ा लेकिन नए नोटों की तरलता के साथ हालात सामान्य होने पर डिजिटल पेमेंट में लगातार गिरावट देखी गई।
- सीएनबीसी आवाज़ चैनल के ट्विटर पोल पर जनता से पूछे गए नोटबंदी से संबन्धित सभी प्रश्नों पर देश की आधे से अधिक जनता ने सरकार के साहस भरे फैसले का समर्थन किया है जिससे पता चलता है कि आधे से अधिक जनता ने विमुद्रीकरण के फैसले पर सरकार का समर्थन किया।

- विमुद्रीकरण के बाद की प्रक्रिया को सफल बनाने में बैंको की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

सुझाव:

शोध अध्ययन में विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार पर विमुद्रीकरण की स्थिति एवं भविष्यमें इसके सुधार से संबंधित सुझाव निम्न हैं-

- कालेधन को रोकने के लिए टैक्स दर को कम किया जाना चाहिए क्योंकि टैक्स बचाने के लिए ही कालेधन की समस्या उत्पन्न होती है।
- डिजिटल पेमेंट के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा कानून का होना बहुत जरूरी है जिससे ऑनलाइन लेन-देन में इस्तेमाल होने वाला डेटा सुरक्षित रहे।
- डिजिटल पेमेंट में लगने वाले अतिरिक्त शुल्क को हटा देना चाहिए जिससे उपयोगकर्ता आसानी से इसका लाभ उठा सकें।
- डिजिटल पेमेंट को पूरे देश में लागू करने के लिए उपयोगकर्ता को इस तकनीक से संबन्धित तथ्यों की जानकारी देना चाहिए।
- टैक्स चोरों या कालेधन रखने वालों के लिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए।
- इन्कम टैक्स विभाग को और अधिक सुविधा सम्पन्न बनाते हुए विभाग में नए अफसरों की भर्ती की जानी चाहिए।
- भुगतान को पूर्णतः डिजिटल करने के लिए उच्च स्तर के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जाए।